भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4920

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

कर्नाटक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति

4920. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): देश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के छात्रों को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय/विभाग
1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
2	अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा योजना (टीसीएस-एससी)	
3	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-ओबीसी)	
4	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस-ओबीसी)	
5	शिक्षा ऋण के लिए ऋण/ऋण-आधारित योजना	
6	व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत शिक्षा ऋण	
7	एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एसटी)	जनजातीय कार्य मंत्रालय
8	एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)	

उपरोक्त के अलावा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएसएस), केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) और पीएम-विद्यालक्ष्मी जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को भी दिया जाता है।

उपरोक्त योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं तथा कर्नाटक सहित किसी भी राज्य के छात्र इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।

*****